

Fourteenth Loksabha**Session : 4****Date : 21-03-2005****Participants : [Singh Shri Prabhunath](#)**

>

Title: Reported malpractices followed in implementing the 'Pradhan Mantri Sadak Yojana'.

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, गत एन.डी.ए. सरकार ने ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी। मुख्य अभियंता स्तर के रिटायर्ड लोगों को उसकी मॉनिटरिंग करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्ति दी गई थी। इसका कारण यह था कि अगर क्वालिटी में कहीं गड़बड़ होगी, तो ठेकेदार को मार्गदर्शन दिया जायेगा और यदि ठेकेदार कोई कार्यवाही नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। एक अंदाज के अनुसार इन पर प्रतिमाह 50 हजार रुपया खर्च पड़ता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिन के लिये 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य दिया जाता है। इसके अलावा उनको आने-जाने का हवाई जहाज का खर्चा भी दिया जाता है। इस प्रकार की मॉनिटरिंग देश के विभिन्न राज्यों - बिहार, सिक्किम, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि में की गई है। उस मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिल गई है। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों के निर्माण में घटिया किस्म का मैटिरियल इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर कार्यवाही हो सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मॉनिटरिंग प्रतिवेदनों पर गम्भीरता से विचार किया जाये। जहां घटिया किस्म का काम हो रहा है, उन प्रतिवेदनों के आधार पर जो ठेकेदार कार्यवाही नहीं करते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाये [इड22ट](#) । जो ठेकेदार उन प्रतिवेदनों के आधार पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना और मिली है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिन मॉनीटर्स ने प्रान्तों के खिलाफ प्रतिवेदन दिये हैं, जहां घटिया किस्म के काम हो रहे हैं, वहां कुछ ठेकेदार और पदाधिकारियों की मिलीभगत से उन प्रतिवेदनों को कूड़ेदान में फेंका गया है और उन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही वहां मॉनीटर्स को काम से वंचित करने की एक साजिश वहां की जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि उन प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्रवाई करे, ताकि वहां जो घटिया निर्माण हो रहे हैं, उनमें सुधार हो सके।

MR. SPEAKER: Certainly this is an important matter.